



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४७] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर १८, १९७२ (कार्तिक २७, १८९४)  
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1972 (KARTIKA 27, 1894)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### नोटिस (NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र १५ फरवरी १९७२ तक प्रकाशित किये गये हैं :—  
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य  
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।  
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

## विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रा- लय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . . . .
1137	—
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि- सूचित विधिक नियम और आदेश . . . . .
1857	—
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक- सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . .
—	1591
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	भाग III—खंड 2—एकम्ब कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस . . . . .
1649	337
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . . .	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . .
—	111
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रश्न समितियों की रिपोर्ट . . . . .	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि- सूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . . .
—	1793
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रा- लयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं 1) . . . . .	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सर- कारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . . . . .
—	229
	पूरक संख्या 47—
	11 नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट . . . . .
	2247
	21 अक्तूबर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . . . . .
	2255

## CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . . . .
1137	—
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Ap- pointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Minis- tries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . . . . .
1857	—
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence . . . . .	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .
—	1591
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Ap- pointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta . . . . .
1649	337
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regu- lations . . . . .	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commis- sioners . . . . .
—	111
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills . . . . .	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertise- ments and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .
—	1793
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Sta- tutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories). . . . .	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . . . . .
	229
	SUPPLEMENT No. 47
	Weekly Epidemiological Reports for week-ending 11th November, 1972 . . . . .
	2247
	Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 21st October, 1972 . . . . .
	2255

## भाग I—खण्ड 1

## (PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 1972

सं० 113-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद  
श्री बिन्धेश्वरी प्रसाद मिश्र,  
पुलिस उप-निरीक्षक,  
पुलिस थाना छत्तरपुर,  
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

30/31 अक्टूबर, 1969 को पुलिस उप निरीक्षक श्री बिन्धेश्वरी प्रसाद मिश्र को दो हूड कांस्टेबलों व बारह कांस्टेबलों के साथ दोनी गांव के गोला चमार के घर पर छापा मारने के लिए तैनात किया गया, जहां डाकू भगवान दास छिपा हुआ था। जब मकान को घेर लिया गया तो डाकू भगवान दास ने मकान के पिछवाड़े के दरवाजे से निकल भागने का प्रयत्न किया किन्तु श्री मिश्र और उनके दल के अन्य व्यक्ति पहले से ही वहां मौजूद थे। पुलिस की उपस्थिति का पता लगने पर डाकू पीछे लौट गया और उसने पिछवाड़े के दरवाजे को अन्दर से बन्द कर लिया तथा मकान के एक छोटे से अंधेरे तथा गन्दे कमरे में मोर्चा संभाला और कमरे के दरवाजे बन्द कर लिये। तब श्री मिश्र मकान की तलाशी लेने के लिए बढ़े और अपने साथ तीन कांस्टेबलों को भी ले लिया। पिछवाड़े का दरवाजा बन्द पाकर वे घूम कर सामने के दरवाजे से मकान के अन्दर गए तथा मकान में तलाशी लेनी शुरू कर दी। उस कमरे में पहुंचने पर जहां डाकू ने शरण ली हुई थी, श्री मिश्र ने डाकू से आत्म-समर्पण करने को कहा। डाकू से कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दरवाजा तोड़ डाला। डाकू ने फट से श्री मिश्र पर गोली चला दी जिससे उनके हाथ में चोट लगी किन्तु श्री मिश्र ने अपना मानसिक संतुलन तथा साहस नहीं खोया और वे डाकू से, जो भरी हुई रिवाल्वर लिए हुए था, भिड़ गए। तब श्री मिश्र ने सहायता के लिए आवाज लगाई। दोन्तीन कांस्टेबल अन्दर आए और डाकू तथा श्री मिश्र को भिड़ते देख वे उपनिरीक्षक की सहायता को बढ़े। वश में करने के प्रयत्न के दौरान डाकू गोली से मारा गया।

इस मुठभेड़ में श्री बिन्धेश्वरी प्रसाद मिश्र ने उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता तथा साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 अक्टूबर, 1969 से दिया जायेगा।

सं० 114-प्रेज/72—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद  
श्री हेमन्तो बरमन,  
लांस नायक, 67800276,  
8वीं बटालियन,  
सीमा सुरक्षा दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

मिर्जा पर्वतीय जिले के रंगीबाई बंचारा स्थान में 16 जनवरी, 1972 की रात्रि के लगभग 9.00 बजे सीमा सुरक्षा दल की एक प्लाटून और नागा विरोधियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान श्री हेमन्तो बरमन को विरोधियों के बचकर भाग निकलने के रास्तों को रोकने के लिए हल्की मशीन गन ग्रुप में तैनात किया गया। जब विरोधियों के मोर्चे पर आक्रमण किया गया तो एक विरोधी ने सीमा सुरक्षा दल के प्लाटून की हल्की मशीन गन पर आक्रमण करने की कोशिश की। श्री हेमन्तो बरमन अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए विरोधी पर टूट पड़े, उसकी राइफल छीन ली और फिर काफी हाथापाई के बाद उसे संगीन से मार डाला।

इस मुठभेड़ में श्री हेमन्तो बरमन ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए प्रशंसनीय साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी, 1972 से दिया जाएगा।

सं० 115-प्रेज/72—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद  
श्री अमिय शेखर मण्डल,  
पुलिस उप-निरीक्षक,  
हावड़ा,  
पश्चिम बंगाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

बाली पुलिस थाने के श्री अमिय शेखर मण्डल 24 मई 1971 को सायं लगभग 5.15 बजे जब आर० टी० वेन ड्यूटी पर थे, तो उन्हें सूचना मिली कि कुछ अपराधी बदामतल्लम बस अड्डे के समीप बस में यात्रा कर रहे एक यात्री की हत्या करने वाले हैं। सूचना प्राप्त होते ही श्री मण्डल ने बाली पुलिस थाने को संदेश भेजा और कुमुक भेजने के लिए कहा, और वह स्वयं बस अड्डे की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि लोग आतंक से इधर-उधर भाग रहे हैं। उन्होंने अपना वाहन वहीं छोड़ दिया और बस अड्डे की ओर अकेले पैदल गए और देखा कि पाइप गन, बमों, तलवारों तथा अन्य हथियारों से लैस लगभग आधे दर्जन युवा लड़कों ने बस को घेर रखा है। तीन लड़के बस के अग्र भाग में ड्राइवर के केबिन में पहले ही प्रवेश कर चुके थे और बस में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को मारते ही वाले थे। श्री मण्डल निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बस के चारों ओर डाले गए घेरे को तोड़ कर आगे बढ़े। अपराधियों ने उन पर आक्रमण किया किन्तु वे अविचलित रहे और आत्म-रक्षा में अपनी रिवाल्वर से दो गोलियाँ चलाई। फिर श्री मण्डल बस के अन्दर गए और अपराधियों में से दो को मार डाला। उन्होंने फिर घायल यात्री को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की, और अपराधियों में से दो को गिरफ्तार भी किया। अन्य अपराधी भाग निकले।

इस मुठभेड़ में श्री अमिय शेखर मण्डल ने उत्कृष्ट साहस तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मई 1971 से दिया जाएगा।

सं० 116-प्रेष/72—राष्ट्रपति कलकत्ता पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद  
श्री अधीर चन्द्र घोष,  
कांस्टेबल,  
विशेष शाखा,  
कलकत्ता।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री अधीर चन्द्र घोष को श्री धीरेज मोदक के लिए, जो 1971 के आम चुनावों में जोराबागान चुनाव क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे, सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। 20 फरवरी, 1971 को शाम को लगभग 6.30 बजे जब श्री घोष बड़दोला पुलिस थाने में स्थित तारक चटर्जी लेन और की० के० पाल एवेन्यू के चौराहे के समीप श्री मोदक के साथ जा रहे थे तो उन पर अचानक एक बम फेंका गया। श्री घोष बम के एक किर्च लगने से जखमी हो गए। श्री घोष एवं श्री मोदक ने तुरंत समीप की एक दुकान में शरण ली। शीघ्र ही उसके बाद तेज धार वाले हथियारों से लैस लगभग एक दर्जन व्यक्ति दुकान में घुसे और उन्होंने उन दोनों की हत्या करने का प्रयत्न किया। श्री घोष

की कमर में चोट लगी। श्री घोष ने तब अपनी रिवाल्वर निकाली और उससे तीन गोलियाँ चलाईं जिसके परिणामस्वरूप दो अपराधी घायल हुए। इसके बाद अपराधी भाग निकले।

इस मुठभेड़ में श्री अधीर चन्द्र घोष ने उदाहरणीय साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 फरवरी 1971 से दिया जाएगा।

सं० 117-प्रेष/72—राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद  
श्री धरमकर अम्बाजी,  
पुलिस उप-निरीक्षक,  
अफजल गंज,  
हैदराबाद,  
आन्ध्र प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

कुछ हरिजनों ने हैदराबाद में गुरुद्वारा गौलिगुडा के पीछे कुछ झोंपड़ियाँ बना ली थीं और वहाँ रह रहे थे। 18 सितम्बर, 1971 को उन झोंपड़ियों का सतिया नामक एक निवासी जब शहर के बस डिपो से अपने घर लौट रहा था, तो जगजीत सिंह नामक एक व्यक्ति ने उसे सिटी होटल के पास रोक लिया। जगजीत सिंह ने सतिया से उसकी अपनी तथा अन्य झोंपड़ियों को हटाने के लिए कहा और यह भी कहा कि गुरुद्वारे के पीछे कोई नहीं रहेगा। उसी समय सतिया का एक मित्र वहाँ से गुजरा और मामले में हस्तक्षेप करने के लिए वहाँ रुक गया। इससे पहले कि सतिया मामले को स्पष्ट कर सके, जगजीत सिंह सतिया के मित्र के हस्तक्षेप से आगबबूला हो गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उससे सतिया के मित्र पर हमला कर दिया। बाद में जगजीत सिंह ने लकड़ी फेंक दी और एक फल विक्रेता के पास से एक चाकू उठा कर ले आया और सतिया के मित्र पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया किन्तु ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जगजीत सिंह अपने घर की ओर भागा और हाथ में तलवार लेकर वापिस आया। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने इस घटना के बारे में अफजलगंज थाने को टेलीफोन द्वारा सूचित कर दिया। सूचना प्राप्त होते ही श्री धरमकर अम्बाजी एक पुलिस दल के साथ घटनास्थल की ओर तुरन्त रवाना हुए। श्री अम्बाजी को देखकर जगजीत सिंह गुरुद्वारे की ओर भागा। श्री अम्बाजी ने गुरुद्वारे के चारों ओर अपने आदमियों को तैनात कर दिया। कुछ समय बाद जगजीत सिंह बाहर आया और श्री अम्बाजी को मार डालने की धमकी दी कि यदि उन्होंने अपने आदमियों को वहाँ से नहीं हटाया। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह

न करते हुए श्री अम्बाजी ने जगजीत सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया किन्तु जगजीत सिंह ने श्री अम्बाजी पर तलवार से वार किया। श्री अम्बाजी ने वार को विफल कर दिया और आक्रमणकारी का हाथ पकड़ लिया। श्री अम्बाजी और जगजीत सिंह के बीच हाथापाई हुई जिसमें श्री अम्बाजी की बायीं कोहनी और बायें हाथ की कनिष्ठिका पर चोट लगी किन्तु उन्होंने आक्रमणकारी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने उसे गिरफ्तार न कर लिया।

इस कार्यवाही में श्री धरमकर अम्बाजी ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 सितम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 118-प्रे०/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री महिपत सिंह,

मण्डल पुलिस निरीक्षक,

जिला दतिया,

मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

डाकू मोहना काछी के गिरोह ने मध्य प्रदेश के जिला दतिया और ग्वालियर के आस-पास के जिलों तथा उत्तर प्रदेश में जालौन व झांसी में आतंक फैला रखा था। 12 फरवरी, 1972 को श्री महिपत सिंह को सूचना मिली कि मोहना काछी का गिरोह गांव उंचिया में है। तुरन्त एक छापा मारने की व्यवस्था की गई तथा गिरोह के छिपने के स्थान को घेर लिया गया। डाकुओं को पुलिस की उपस्थिति का पता चल गया तथा उन्होंने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। श्री महिपत सिंह गोली लगने से बाल-बाल बचे किन्तु वह अविचलित रहे और उन्होंने डाकुओं से आत्म-समर्पण करने को कहा। किन्तु डाकू रात भर गोलियां चलाते रहे और प्रातः लगभग 4.15 बजे उन्होंने भारी गोलाबारी की आड़ में बचकर भाग निकलने का प्रयत्न किया। अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए श्री महिपत सिंह ने डाकुओं के प्रयत्न को विफल कर दिया और गिरोह के सरदार मोहना काछी तथा एक और डाकू को गोली से मार डाला। उन्होंने एक डाकू को जीवित भी पकड़ लिया।

इस मुठभेड़ में श्री महिपत सिंह ने उत्कृष्ट साहस एवं पहलुशक्ति का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 फरवरी, 1972 से दिया जाएगा।

पे० ना० कृष्णमणि, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

## मंत्रिमण्डल सचिवालय

### (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 1972

#### नियम

सं० फा० 6/51/72-के० सं० (1)—निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1971 के नियम 5 तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 की केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में (रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली 1971 के नियम 4 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में (1) निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों का, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात् किन्तु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्रदान किया गया था अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए थे, परन्तु जिन्हें उस तारीख की अथवा उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया था और (II) भूतपूर्व सैनिकों का उनके लिए क्रमशः वर्ग-I तथा वर्ग-II में जाने वाली सेवाओं/पदों में आरक्षित रिक्तियां भरने के प्रयोजन हेतु चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1973 में ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित नियम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। उपर्युक्त निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1971 तथा भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सेवाएं तथा पद श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 में रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1971 क्रमशः 29 जनवरी, 1974 तथा 1 जुलाई, 1974 से प्रभावी नहीं रहेगी जब तक कि सरकार द्वारा यह अवधि बढ़ा न दी जाए।

#### वर्ग—1

#### श्रेणी-I की सेवाओं/पद

- (i) भारतीय विदेश सेवा (ख) में (सहायक) का सामान्य काडर ग्रेड IV;
- (ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा-सहायक ग्रेड;
- (iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा-सहायक ग्रेड;
- (iv) निर्वाचन आयोग के कार्यालय, नई दिल्ली, में सहायक के पद;
- (v) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय, नई दिल्ली, में सहायक के पद;
- (vi) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली, में सहायक के पद;
- (vii) पर्यटन विभाग, नई दिल्ली, में सहायक के पद, और
- (viii) भारत सरकार के अन्य विभागों और सम्बद्ध से कार्यालयों में, जो भारतीय विदेश सेवा (ख)। केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, सहायक के पद।

## वर्ग—2

## श्रेणी-III सेवाओं/पद

- (i) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा-ग्रेड IV (सहायक), और
- (ii) भारत सरकार के अन्य विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में, जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, सहायक के पद ।

**नियम—2** के उपबन्धों के अधीन कोई उम्मीदवार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगी हो सकता है । उम्मीदवार जिन सेवाओं/पदों के बारे में वह चाहता है कि उस पर विचार किया जाए, उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर दें ।

**टिप्पणी 1—**उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि जितनी सेवाओं/पदों के लिए वे चाहते हैं कि उन पर विचार किया जाए उनके अधिमान क्रमों का अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख करें । उन को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे जिन सेवाओं/पदों को चाहते हैं उनका भी उल्लेख करें ताकि योग्यता-क्रम से उनके क्रम को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनके अधिमान पर उचित रूप से ध्यान दिया जा सके ।

**टिप्पणी 2—**उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र में सेवाओं/पदों के लिए जिस अधिमान क्रम का मूल रूप से उल्लेख किया है उसमें कोई बात जोड़ने या परिवर्तन करने के उस अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जो 30 नवम्बर, 1973 को या इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में न पहुँच जाएगा ।

2. (क) आपात-कालीन आयुक्त/अल्प कालीन सेवा आयुक्त अधिकारी केवल वर्ग-I में उल्लिखित श्रेणी-2 के सेवाओं/पदों में सहायकों के पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ।

(ख) भूतपूर्व सैनिक केवल वर्ग-II से उल्लिखित श्रेणी-III के सेवाओं/पदों में सहायकों के पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे ।

3. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार होगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतने रिक्त स्थान आरक्षित किए जाएंगे जितने भारत सरकार निर्धारित करे ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जाति/आदिम जाति में से किसी एक से है; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान अनुसूचित जाति (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 तथा संविधान अनु० आ० जाति

(भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951 संविधान (जम्मू तथा काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति/आदेश, 1959 संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन व दियू) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा दमन व दियू) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1970 ।

4. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

5. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित वर्गों के वे आपातकालीन आयुक्त तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी इस परीक्षा में बैठ सकेंगे, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के बाद किन्तु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त हुआ हो अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों परन्तु जिन्हें इस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ हो :—

- (i) वे अधिकारी जो इस अधिसूचना की तारीख से पहले 1972 में निर्मुक्त हो चुके हैं अथवा इस के बाद 1973 के अन्त तक निर्मुक्त होने हैं ।
- (ii) वे अधिकारी, जो नियम 12 के उपबन्धों की सीमा तक तथा उनके अनुसार उस नियम में उल्लिखित हैं ।

**टिप्पणी 1—**इन नियमों के प्रयोजन के लिए “निर्मुक्त” का अभिप्राय :—

- (i) निर्मुक्त के निर्धारित वर्ष के अनुसार निर्मुक्त,
- (ii) सैनिक सेवा के कारण विकलांग होने या सैनिक सेवा द्वारा गम्भीर स्थिति होने के कारण अशक्त होने का अभिप्राय सशस्त्र सेनाओं से निर्धारित अवधि की सेवा, के बाद निर्मुक्त से है, और इसका अभिप्राय प्रशिक्षण के दौरान या इसके समाप्त होने के बाद या वास्तविक सेवा में लिए जाने के पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को सम्मिलित करने के लिए प्रदान किए गए अल्प कालीन सेवा कमीशन की अवधि में या इसके समाप्त होने के बाद निर्मुक्त से नहीं है, और न ही इसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारी आते हैं, जो कवाचार या अदक्षता या अपने निजी अनुरोध पर निर्मुक्त किए गए हैं ।

**टिप्पणी 2—**“निर्मुक्त के नियत वर्ष” अभिव्यक्ति का अभिप्राय :—

- (i) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में उस वर्ष से है, जिसमें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वे निर्मुक्त किए जाने हैं ;

1(ii) अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सम्बद्ध में उस वर्ष से है, जिसमें अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में उनकी, यथा-स्थिति, 3 या 5 वर्ष की सामान्य अवधि समाप्त होनी है ।

टिप्पणी 3—यदि किसी व्यक्ति को, आवेदन-पत्र भेजने के बाद, सशस्त्र सेनाओं में स्थायी आयुक्ति दे दी जाएगी, या वह सशस्त्र सेना से त्याग पत्र दे वेगा, या दुर्व्यवहार, अकुशलता के कारण या अपने स्वयं के अनरोध पर उसे सेवाओं से निर्मुक्त कर दिया जाएगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

टिप्पणी 4—सशस्त्र सेनाओं के वालंटियर रिजर्व फोर्स के अधिकारी जिन्हें अस्थायी सेवा के लिए बुला लिया जाए, इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे ।

6. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन शर्तें पूरी करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिक इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पणी 5—इन नियमों के प्रयोजन के लिए “भूतपूर्व सैनिक” का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी पद पर (चाहे युद्धकारी के रूप में या अन्य प्रकार से) 15 जनवरी, 1973 को निरन्तर छः महीने से कम निरन्तर सेवा न कर चुका हो, और

(i) कदाचार या अदक्षता के कारण अपदस्थ या सेबोन्मुख न होकर निर्मुक्त हुआ हो या ऐसी निर्मुक्ति निलम्बित होने तक आरक्षित सेना में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, या

(ii) जिसे निर्मुक्ति की पात्रता के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि समाप्त करने के लिए 15 जनवरी, 1973 को कुछ महीने से अधिक सेवा करनी हो या ऐसी निर्मुक्ति निलम्बित होने तक आरक्षित सेवा में स्थानान्तरित कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए “संघ की सशस्त्र सेनाओं” का अभिप्राय संघ की नौसेना, सेना या वायु सेनाओं से है जिसमें भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेनाएं भी सम्मिलित हैं ।

7. (1) उम्मीदवार या तो :—

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) सिक्किम की प्रजा, या
- (ग) नेपाल की प्रजा, या
- (घ) भूटान की प्रजा, या
- (ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या
- (च) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, (पहले जिसका नाम सिंघोन

था) तथा पूर्वी अफ्रिका के केनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका तथा जंजीबार) देशों से आया हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

परन्तु यह और भी कि ऊपर की (ग), (घ), (ङ) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य काडर (सहायक) के ग्रेड 4 में नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे ।

(2) परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने के अर्धान्तर अन्तिम (प्राविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

8. (क) आपातकालीन आयुक्त/आल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी, जो उपर्युक्त 5 के अनुसार परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता है तो यह आवश्यक है कि सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ करना पड़ता था) वाली वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु पूरे 24 वर्ष न हुई हो,

शर्त यह है कि निम्नलिखित नियम 9(ख) में उल्लिखित विधि अनुसार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उपर्युक्त तारीख को निम्नलिखित आयु न हुई हो :—

(i) 24 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में आने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाता था) अगले वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो,

(ii) 23 वर्ष, जब कि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद) प्रशिक्षण प्रारंभ करना पड़ता था) अगले वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(iii) 22 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमी-

शन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ करना पड़ता था) अगले वर्ष के दूसरे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो।

- (iv) 21 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ करना पड़ता था) अगले वर्ष के तीसरे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो।
- (v) 20 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ करना पड़ता था) अगले वर्ष के चौथे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो।
- (vi) 19 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करना या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ करना पड़ता था) अगले वर्ष के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो।

(ख) कोई भूतपूर्व सैनिक, जो उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार परीक्षा में प्रवेश चाहता है तो यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1973 को उसकी आयु 20 वर्ष हो गयी हो तथा सशस्त्र सेना में कुल सेवा तीन वर्ष जोड़ कर भी 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी:—किसी भूतपूर्व सैनिक की सशस्त्र सेनाओं में आह्वान पर सेवा, भी उपर्युक्त नियम 8(ख) के लिए सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा समझी जाएगी।

(ग) उपर्युक्त सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा और भी छूट के योग्य होगी :—

- (i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आया वास्तव में विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आया वास्तव में विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार भारत श्री लंका समझौता अक्टूबर, 1964 के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका (पहले जिसका नाम सिलोन था) से वास्तव में प्रत्यावर्तित हो कर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो और भारत श्री लंका (पहले जिसका नाम सिलोन था) समझौता अक्टूबर, 1969 के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्री लंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित हो कर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दिवू संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार कैनिया, उगांडा और संयुक्त राज्य गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तंजानिया तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप का भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक, तीन वर्ष ;

(viii) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद वास्तव में बर्मा से प्रत्यावर्तित हुआ भारतीय वंशज हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद वास्तव में बर्मा से प्रत्यावर्तित हुआ भारतीय मूल का व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,



(x) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं का सैनिक हो जो अन्य देश के साथ युद्ध में या किसी आक्रांत क्षेत्र में अश्वत हुआ हो और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किया गया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(xi) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं का सैनिक हो जो अन्य देश के साथ युद्ध में या किसी आक्रांत क्षेत्र में अश्वत हुआ हो और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किया गया हो और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक, और

(xii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर तक फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक,।

(घ) उपर्युक्त उप-वैरा (क) में उल्लिखित निर्धारित आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी :—

(i) यदि उम्मीदवार पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो, और उसने सशस्त्र सेनाओं में 1963 में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हो या जिसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद प्रशिक्षण रहा हो) तो तीन वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और साथ ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और 1963 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हो या उसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) तो 8 वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का निवासी हो और 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हो या उसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो), तो 4 वर्ष और यदि उम्मीदवार श्रीलंका (पहले जिसका नाम सीलोन था) से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ भारतीय नागरिक हो और 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हो या उप कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो), तो 3 वर्ष,

टिप्पणी:—1. नियम 8(घ) तथा 8(घ) (ii) में विहित उपबन्ध, नियम 8(क) के परन्तुक में क्रम संख्या (ii), (iii), (iv), (v) तथा (vi) पर उल्लिखित उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी:—2. नियम 8(घ) (iii) तथा 8(घ) (iv) में विहित उपबन्ध, नियम 8(क) के परन्तुक में क्रम संख्या (iii), (iv), (v) तथा (vi) पर उल्लिखित उन उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होंगे जिसने 1963 के बाद कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हो या जिसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो),

नियम 8(घ) (iii) तथा 8(घ) (iv) में विहित उपबन्ध, नियम 8(क) के परन्तुक में क्रम संख्या (ii) पर उल्लिखित उन उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होंगे, जिसने 1964 के बाद कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हो या जिसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो)।

(ड०) गोआ दमन दियू के उन स्वाधीनता सेनानियों को, जो गोआ दमन दियू की सरकार के कर्मचारी नहीं थे और उन्होंने मुक्ति संघर्ष में भाग लिया था और उसके फलस्वरूप भूतपूर्व पुर्तगाली प्रशासन के अधीन कम से कम छः मास के लिए कारावास अथवा हिरासत में रहें हों, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि 1 जनवरी, 1972 को उनकी आयु 35 वर्ष की न हुई हो।

टिप्पणी :—नियम 8(ड०) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उपरोक्त नियम 8(ग) के अन्तर्गत मिलने वाली आयु में छूट के हकदार नहीं होंगे।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी में छूट नहीं दी जायेगी।

9. (क) उपर्युक्त नियम 5 के अनुसार आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-1 में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए, या उसमें परिशिष्ट-1-क में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिए।

बशर्ते कि:—

(i) विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त योग्यताओं में से कोई भी योग्यता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिस के स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी

विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट-1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

टिप्पणी:—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस नियम के उप नियम (क) के अनुसार इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार किसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र दे सकता है, बशर्त कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाय। ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी, और यदि वे उक्त परीक्षा के पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है।

(ख) यदि कोई उम्मीदवार, जो सशस्त्र सेनाओं में आपात कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त सेवा के लिए उम्मीदवार की हैसियत से सेवाओं के प्रवरण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के दौरान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, अर्थात् विश्वविद्यालय। इस नियम के उपनियम (क) में निर्धारित किसी योग्यता के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्ध विद्यालय, में शैक्षिक अध्ययन कर रहा हो, किन्तु सशस्त्र सेनाओं में जाने कारण शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कोई अर्हता प्राप्त नहीं कर सका हो तो वह भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

(ग) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार इस परीक्षा में प्रवेश चाहता है तो, उसके पास परिशिष्ट-1 में सम्मिलित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या परिशिष्ट-1 -क में उल्लिखित कोई योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिए।

नोट 1. यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र दे सकता है, बशर्त कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम (प्रोविजनल) मानी जाएगी, और यदि वे उक्त परीक्षा के पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की

तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है।

नोट:—2. विशेष मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसमें कोई भी उपर्युक्त अर्हताएं न हों, शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है, बशर्त कि उसने अन्य सस्थाओं में से किसी के द्वारा ली गई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उस के आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

नोट:—3. जो उम्मीदवार अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों, पर जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्रीयां ली हों, जिन्हें परिशिष्ट-1 में शामिल नहीं किया गया हो, वे भी आयोग को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षाओं में बैठने के लिए दो बार से अधिक बार बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह प्रतिबन्ध 1971 की परीक्षा से गिना गया।

11. वर्ग-1 (देखें नियम 2) में दी गई सेवाओं और पदों के लिए प्रतियोगिता करने वाले किसी उम्मीदवार को अपनी निर्मुक्ति के वर्ष में और अपनी निर्मुक्ति के वर्ष से अगले वर्ष में ली जाने वाली परीक्षा में क्रमशः अपने पहले और दूसरे अवसरों के रूप में अवश्य बैठना चाहिए।

12. नियम 11 में दी गई किसी बात के बावजूद:—

(i) ऐसा कोई भी उम्मीदवार जिसे 1971 की परीक्षा के आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विहित अन्तिम तारीख के पश्चात् 1971 के दौरान सैनिक सेवा के कारण हुई विक्लांगता अथवा विक्लांगता के गंभीर रूप कारण करने के कारण असम्य ठहराया गया हो, 1973 में होने वाली परीक्षा अपने दूसरे अवसर के रूप में दे सकता है।

(ii) ऐसा कोई उम्मीदवार जिसे 1972 की परीक्षा के आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विहित अन्तिम तारीख के पश्चात् 1972 के दौरान सैनिक सेवा के कारण हुई विक्लांगता अथवा विक्लांगता के गंभीर रूप कारण करने के असम्य ठहराया गया हो, 1973 में होने वाली परीक्षा अपने पहले अवसर के रूप में दे सकता है।

(iii) कोई भी आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी, जो सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 10 जनवरी, 1968 से पहले सम्मिलित हुआ हो परन्तु उसे 10 जनवरी, 1968 को या उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ हो, निम्नलिखित शर्तों

के अधीन 1973 में होने वाली परीक्षा दे सकता है :—

- (क) अपने दूसरे अवसर के रूप में, यदि 1972 से पहले निर्मुक्त हुआ हो ;
- (ख) अपने पहले अवसर के रूप में, यदि 1972 के दौरान निर्मुक्त हुआ हो ;
- (ग) अपने पहले अवसर के रूप में, यदि वह 1971 की परीक्षा के लिये आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख के पश्चात् 1971 के दौरान सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा विकलांगता के गंभीर रूप धारण करने के कारण अमान्य ठहराया गया हो ।

टिप्पणी 1—उपरोक्त (i) तथा (iii) (ग) में दिये गये उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 1971 में निर्मुक्त होना था ।

टिप्पणी 2—उपरोक्त (ii) में दिया गया उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें 1972 में निर्मुक्त होना था ।

टिप्पणी 3—ऐसे उम्मीदवार जो इस नियम के उपबन्धों के अनुसार 1974 में अपना दूसरा अवसर लेने के पात्र हैं, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं यदि सरकार द्वारा इन नियमों के उपबन्धों की अवधि 28 जनवरी, 1974 के आगे बढ़ा दी जाती है ।

13. ऐसा कोई भी व्यक्ति—

- (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा
- (ii) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा :

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार यदि इस ओर आश्वस्त हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के बन्धन से छूट दे सकती है ।

14. सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारी उम्मीदवार को इस परीक्षा के लिये अपना आवेदन पत्र संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में भेजने के लिये अपनी यूनिट के कमांडिंग आफिसर को प्रस्तुत करना चाहिये ।

सरकारी सेवारत अन्य सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे स्थायी अथवा अस्थायी पद पर हों अथवा अनियत अथवा चिहाड़ी पर रखे कर्मचारियों को छोड़कर, कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त

हों, परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी होगी ।

15. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन न कर सके । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा ली जायगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किये जाने की संभावना हो ।

टिप्पणी :—रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के संबंध में रक्षा सेवाओं के सैन्य विषयन मैडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिये पर्याप्त माना जायगा ।

16. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाय कि उम्मीदवार इस सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है ।

17. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

18. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

19. यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है ।

20. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किये हों या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किये हों जिनमें कोई हेरफेर किया गया है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई प्रमुख तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में बैठने के लिये किसी और अनियमित या अनुचित तरीके से काम लिया है या परीक्षाभवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसे वांडिक अभियोजित (क्रिमिनल प्रासिक्च्युशन) किये जाने के अतिरिक्त—

(क) उसे हमेशा के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये :—

- (i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिये ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इंटरव्यू में शामिल होने से आयोग रोक सकता है, और
- (ii) केंद्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

## 21. परीक्षा के बाद —

- (क) वर्ग-1 में सम्मिलित सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की गुणानुक्रम से सूची बनायेगा उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर अर्हक उम्मीदवारों की आयोग नियुक्ति के लिये सिफारिश करेगा।
- (ख) वर्ग 2 में सम्मिलित सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की गुणानुक्रम में सूची बनायेगा, और उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिये निश्चित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जिन उम्मीदवारों को परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त देखेगा, उनकी नियुक्ति के लिये सिफारिश करेगा,

परन्तु यदि सामान्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिये आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हों, नियुक्ति के लिये सिफारिश किये जा सकेंगे, बशर्ते ये उम्मीदवार इस सेवा/पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त हों।

22. यदि परीक्षा के परिणाम आधार पर वर्ग 1 की सेवाओं/पदों में निर्युक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों और वर्ग 2 के सेवाओं/पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्त स्थान को भरने के लिये अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो न भरे गये रिक्त स्थान इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित विधि से भरे जायेंगे।

23. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनके परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

24. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियों के समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र भरते समय वर्ग (नियम 1 का संदर्भ) में सम्मिलित विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये, जिसके संबंध में उसे परीक्षा में प्रवेश दिया गया था, बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान दिया जायगा।

25. नियुक्तियां दो वर्ष की परीचीक्षा अवधि पर की जायेंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परीचीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

26. उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में अथवा 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे नियम अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक

ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक अधिकारी न होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाय और परीक्षा पास कर लेने पर या उसके छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जाय कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायगा।

27. केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (बी०), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों और भारत के चुनाव आयोग तथा पर्यटन विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग और संसद-कार्य विभाग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट-3 में संक्षेप में दी गई हैं।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

## परिशिष्ट 1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची  
(देखिये नियम 9)

भारतीय विश्वविद्यालय :

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केंद्रीय या राज्य विधान मंडल के अधिनियम से नियमित किया गया हो या अन्य शिक्षा संस्थायें जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किये गये हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य घोषित किये गये हों।

बर्मा के विश्वविद्यालय :

रंगून विश्व-विद्यालय

मांडले विश्वविद्यालय

इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय :

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, हरदम, लीड्स, लिवरपूल, मैनचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शैफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय :

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और सेंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय :

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज), नेशनल यूनिवर्सिटी आफ आयरलैंड, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बैलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय :

पंजाब विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय।

बंगला देश के विश्वविद्यालय :

ढाका विश्वविद्यालय, राजशाही विश्वविद्यालय।

नेपाल के विश्वविद्यालय :

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू।

## परिशिष्ट-1-क

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये मान्यताप्राप्त योग्यतायें (देखिये नियम 9)।

- (1) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की “अलैकार पववी”
- (2) काशी विद्यापीठ, वाराणसी का “शास्त्री”
- (3) फ्रांसिसी परीक्षा “प्रापेदलीक” (Propedeutique)
- (4) उच्चतर ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् को ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
- (5) विश्वभारतीय विश्वविद्यालय का ग्राम सेवा डिप्लोमा।
- (6) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का वाणिज्य में डिप्लोमा।
- (7) केंद्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं और पदों की भर्ती के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा।
- (8) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, की खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।
- (9) श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, पांडिचेरी का “उच्चतर पाठ्यक्रम”, यदि पूर्ण छात्र (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
- (10) शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या पुराना शास्त्री या सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी एक विषय सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा हो, अर्थात् वागणासेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का वरिष्ठ शास्त्री।
- (11) मानवशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस के किसी उच्च शिक्षण संस्थान का समकक्ष स्नातक डिप्लोमा बिना प्रथम वैज्ञानिक निबन्ध के परन्तु राज्य परीक्षायें की गई हों।

## परिशिष्ट-II

## 1. प्रतियोगिता परीक्षा की रूपरेखा :

- (क) निम्नलिखित पैरा 2 में उल्लिखित तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसके कुल 400 अंक होंगे।
- (ख) आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में, सशस्त्र सेनाओं में सेवा-रिकार्ड का मूल्यांकन जिसके कुल 100 अंक होंगे।

## 2. परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध	100	2 घण्टे
2. सामान्य अंग्रेजी	200	3 घण्टे
3. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है	100	2 घण्टे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है।
4. उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 3 अथवा दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना होगा।

नोट :—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा, उसी प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं।

नोट :—उक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के खाना 10 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

एक बार किया गया विकल्प अंतिम समझा जाएगा और इस कालम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक (क्वालीफाइंग अंक) निर्धारित कर सकता है।
7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।
8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत अंक काट दिए जाएंगे।
9. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई भाषाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

## अनुसूची

## परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. निबन्ध : दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।
2. सामान्य अंग्रेजी :

(1) सारलेखन और मसौदा लेखन—अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे आम तौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिए अवतरण (पैसेज) दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें उस सामग्री का समुचित उपयोग करते हुए पत्रों ज्ञापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जाएगा।

(2) पर्यायों, विलोभी, शब्दों तथा पदों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य मूलों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।

(3) शब्द भेद (पार्ट्स आफ स्पीच), वाक्य विश्लेषण वाक्य रचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट और इन् डायरेक्ट स्पीच)।

नोट :—प्रश्न पत्र 2 में सार लिखने के लिए 75 अंक, मसौदा लेखन के लिए 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिए 50 अंक होंगे :

प्रश्न पत्र 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है। वाक्य विन्यास तथा योजना, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक पर ध्यान दिया जाएगा।

3 सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है :

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पदों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

### परिशिष्ट-III

उन सेवाओं/पदों संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

(i) भारतीय विदेश सेवा (बी)

विदेश मंत्रालय में और विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक कांसुली एवं वाणिज्यिक दूतावासों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-4 में सम्मिलित हैं। ग्रेड-4 के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड सम्मिलित हैं :—

ग्रेड	पद	वेतनमान
ग्रेड-1	मुख्यालय में अवर सचिव, विदेश में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में प्रथम और द्वितीय सचिव।	रु० 900-50-1250।
एकीकृत ग्रेड	मुख्यालयों में सहायकारी और अनुभाग अधिकारी/विदेशों में स्थित दूतावासों	रु० 350-25-500-30-590-
2 और 3	और केन्द्रों में उप कांसुल और रजिस्ट्रार	रु० 400-30-800-40-900-30-830-35-900।
ग्रेड-4	मुख्यालय में तथा विदेशों में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में सहायक।	रु० 210-10-270-15-300-40-450-50-530।

टिप्पणी—एकीकृत ग्रेड-II और III में पदोन्नत सहायकों को कम से कम 400 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है।

2. भारतीय विदेश सेवा (बी) के संवर्ग के ग्रेड 4 (सहायक) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रारम्भ में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्त किया जाएगा फिर भी, वे अन्यथा पात्र होने पर अपनी

बारी में, भारतीय विदेश सेवा (बी) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 के अनुसार स्थायी किए जायेंगे, किन्तु यह अभिस्थायी रिक्त स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर होगा। उम्मीदवारों की ग्रेड-4 में नियुक्ति सामान्यतया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित क्रमानुसार की जायगी यदि विदेश सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर उन्हें अस्वीकार न किया गया हो। विदेश सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता को निर्धारण करने के लिए उम्मीदवार को, एक चयन ग्रेड जो विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित किया जाएगा के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

3. भारतीय विदेश सेवा (बी) में सामान्य संवर्ग के ग्रेड-4 में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परीक्षाधीन रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों। प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाओं पास न करने के फलस्वरूप परीक्षाधीन को नौकरी से निकाला जा सकता है।

4. भारतीय विदेश सेवा (बी) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्त किए जाने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें भारत अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किया जाय सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (बी) के सदस्य अब भारत में सेवामुक्त हों तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो अन्य केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं। जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त किए जाते हैं तो कुछ रियायतें पाने के हकदार होंगे जैसे—उनके लाभ के लिए सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित स्केल के अनुसार विदेश सेवा, निशुल्क फर्नीचरयुक्त निवास स्थान, बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता और उनके तथा उनके परिवार इत्यादि के लिए यात्रा भाड़ा इत्यादि किया जाता है। ये रियायतें ऐसे सामान्य निर्णयों के अनुसार जो कि सरकार लेती है वापिस ली जा सकती है, संशोधित की जा सकती है अथवा बढ़ाई जा सकती है।

6. भारतीय विदेश सेवा (बी) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन भी होंगे जो सेवा पर लागू होने के लिए सरकार भविष्य में बनाए।

7. भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड-4 में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा ब) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी :—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1961 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (बी) के ग्रेड-1 के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा (ए) के वरिष्ठ वेतन मान में पदोन्नति के लिए 900-50-1000-60-1600-50-1800 के वेतनमान में सीमित कोटा उपलब्ध है।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

- (1) सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष) —  
रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800।
- (2) ग्रेड 1 (अवर सचिव या समकक्ष) रु० 900-50-1250।
- (3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 350-25-500-30-590-६० रु० ३०-800-६० रु० ३०-830-35-900।
- (4) सहायक ग्रेड—रु० 210-10-270-15-300-६० रु० १०-15-450-६० रु० २०-530।

नोट :—जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रुपए प्रतिमास वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परीक्षा पर रखा जाएगा। इस परीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो वे अपनी इस नियुक्ति के बाव भारतीय विदेश सेवा (बी) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का वाचा नहीं कर सकेंगे।

### (III) रेलवे बोर्ड सचिवालय :

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का सम्बन्ध है, रेलवे मन्त्रालय में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 द्वारा नियमित होती हैं, जो मोटे तौर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के समान ही हैं।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल हैं :—

- (i) चयन ग्रेड : संयुक्त निदेशक/उप सचिव, रेलवे बोर्ड के ग्रेड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800। के अधिकारियों द्वारा समय समय पर धारण किए जाते हैं।
- (ii) उप-निदेशकों का ग्रेड : रु० 900-50-उप-निदेशक रेलवे बोर्ड 1250-विशेष भेतन के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड 200 रुपए मासिक। सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय समय पर धारण किए जाते हैं।

(ख) ग्रेड 1: सहायक निदेशक रु० 900-50-1250 और अवर सचिव

(iii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड रु० 350-25-500-30-590-६० रु० ३०-800-६० रु० ३०-830-35-900।

(iv) सहायक ग्रेड रु० 210-10-270-15-300-६० रु० १०-15-450-६० रु० २०-530।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं उन्हें कम से कम 400 रुपए प्रतिमास वेतन दिया जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेलवे मन्त्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारियों का स्थानान्तरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा की भांति अन्य मन्त्रालयों को नहीं हो सकता।

(घ) सहायकों के रूप में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

(ङ) सहायक इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(च) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी :—

- (i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और
- (ii) जिस दिन कार्य संभालें उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत निधि में अभिदान करेंगे।

(छ) रेल मन्त्रालय में नियुक्त कर्मचारियों की अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही पास और सुविधा टिकट आदेश की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ज) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में इन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

#### (IV) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा :

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे पांच ग्रेड हैं :

(1) संयुक्त निदेशक क्लास-1	रु० 1300-60-1600।
(2) वरिष्ठ सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-1)	रु० 1100-50-1400
(3) सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-1)	रु० 740-30-800-50-1150।
(4) सहायक सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी II राजपत्रित) :	रु० 350-25-500-30-590-६० रु०-30-800।
(5) सहायक (श्रेणी-II अराजपत्रित)	रु० 210-10-270-15-300-६० रु०-15-450-६० रु०-20-530।

नोट :—सहायक के ग्रेड अधिकारी को सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड पर पदोन्नत होने पर सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 400 रुपए का आरम्भिक वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को सेवा मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल अन्तर सेवा संगठनों में से किसी एक में

नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं उनका, ऐसी नियुक्ति के उपरान्त, इस सेवा के बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

#### (V) निर्वाचन आयोग, भारत :

चुनाव आयोग में सहायकों के पद का वेतन मान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के पदों के समान ही रु० 210-10-270-15-300-६० रु०-15-450-६० रु०-20-530 है। फिर भी यह पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल नहीं है तथा इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवामुक्त किया जा सकेगा।

3. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर हर प्रकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

4. सहायक इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे। इसके आगे दो और ऊंचे ग्रेड हैं :—

1. अनुभाग अधिकारी ग्रेड :	रु० 350-25-500-30-590-६० रु०-30-800-६० रु०-30-830-35-900।
2. अवर सचिव ग्रेड :	रु० 900-50-1250

#### (VI) पर्यटन विभाग :

पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों का वेतनमान रुपये 210-10-270-15-300-६० रु०-15-450-६० रु०-20-530 है जैसे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड चार के लिए निर्धारित है। किन्तु ये पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सम्मिलित नहीं हैं और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते।



सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे, और इस अवधि में उन्हें भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा। तथा विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति दिखाने में या परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रखने का परिणाम सेवा से मुक्त हो सकता है।

परिवीक्षा की समाप्ति पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, उसकी नियुक्ति पर पुष्टि कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि आगे और उस सीमा तक बढ़ायी जा सकती है जितनी कि सरकार आवश्यक समझे।

समय समय पर इस विषय में जारी किए जाने वाले नियमों के अधीन, सहायक, सहायक निदेशक (प्रशासन) के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे जिसका वेतनमान रुपये 400-25-500-30-590-द० रो०-30-800 है।

#### (VII) केन्द्रीय सतर्कता आयोग :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सहायकों के पदों का वेतनमान वही है जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-IV के लिए विहित है, अर्थात् रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 फिर भी यह पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल नहीं है तथा इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षा की सहायक अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

3. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है।

4. सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नतियां पा सकेंगे। इस समय 3-331GI/72

इसके आगे और ऊंचे ग्रेड निम्नलिखित हैं :—

1. अनुभाग अधिकारी ग्रेड :—	रु० 350-(400)-
(श्रेणी-II राजपत्रित)	25-500-30-590-
	द० रो०-30-800-
	द० रो०-30-830-
	35-900।

2. अवर सचिव ग्रेड :—	रु० 900-50-1250।
(श्रेणी-I)	

#### (VIII) संसद कार्य विभाग :

संसद कार्य विभाग में सहायकों के पदों का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के पदों के समान ही रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 है। फिर भी, यह पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल नहीं है तथा इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षा की सहायक अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

3. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है बशर्ते कि स्थायी पद उपलब्ध हों और स्थायीकरण के लिए उसकी बारी आ गई हो या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है।

4. सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नतियां पा सकेंगे। इसके आगे दो और ऊंचे ग्रेड हैं :

1. अनुभाग अधिकारी ग्रेड :—	रु० 350-25-500-
	30-590-द० रो०-
	30-800-द० रो०-
	30-830-35- 900
	(श्रेणी-II)

2. अवर सचिव ग्रेड :—	रु० 900-50-
	1250 (श्रेणी-I)

टिप्पणी :—अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत किये गये सहायक ग्रेड के अधिकारी को अनुभाग अधिकारी ग्रेड के वेतनमान में 400 रु० न्यूनतम आरम्भिक वेतन प्रदान किया जायेगा।

**PRESIDENT'S SECRETARIAT***New Delhi, the 2nd November 1972*

No. 113-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

*Name and Rank of the Officer*

Shri Bindheswari Prasad Mishra,  
Sub-Inspector of Police,  
Police Station Chhatarpur,  
Madhya Pradesh.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 30th/31st October, 1969, Shri Bindheswari Prasad Mishra, Sub-Inspector of Police, along with two Head Constables and twelve Constables, was deputed to raid the house of one Gola Chammur of Village Doni, where dacoit Bhagwandass was hiding. When the house was surrounded, dacoit Bhagwandass tried to escape through the backdoor of the house but Shri Mishra and the other men of his force were already in position there. Realising the presence of the police, the dacoit retraced his steps, bolted the back door from inside and took position in a small dark and dingy room in the house and closed the doors of the room. Shri Mishra then led a party of two to three constables in order to search the house. On finding the back door locked, he walked around and entered the house from the front door and started a search of the house. On reaching the room where the dacoit was taking shelter, Shri Mishra asked the dacoit to surrender. On getting no response from the dacoit, he broke open the door in disregard of his personal safety. The dacoit instantly opened fire on Shri Mishra and injured him on his arm but Shri Mishra did not lose his balance of mind and courage and grappled with the dacoit who was carrying a loaded revolver. Shri Mishra then shouted for help. Two/three constables came in and on seeing the dacoit and Shri Mishra fighting with each other, they came to the assistance of the Sub-Inspector. The dacoit was shot dead in the process of being over-powered.

In this encounter Shri Bindheswari Prasad Mishra displayed high sense of duty and courage.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st October, 1969.

No. 114-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

*Name and Rank of the Officer*

Shri Hemonto Borman,  
Lance Naik, 67800276,  
80th Battalion,  
Border Security Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

In an encounter that took place between a Platoon of the Border Security Force and the Naga hostiles at about 2100 hrs. on 16th January, 1972 at Rangibai Bichara in Mizo Hills District, Shri Hemonto Borman was deployed in the LMG group for blocking the escape routes of the hostiles. When the position of the hostiles was assaulted, one of the hostiles attempted to attack the LMG of the Border Security Force Platoon. Shri Hemonto Borman in disregard to his personal safety jumped over the hostile, snatched away the rifle from him and bayoneted him to death after a good deal of hand to hand fighting.

In this encounter Shri Hemonto Borman displayed commendable courage in disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th January, 1972.

No. 115-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

*Name and Rank of the Officer*

Shri Amiya Sekhar Mondal,  
Sub-Inspector of Police,  
Howrah,  
West Bengal.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

While on R.T. Van duty on the 24th May, 1971 at about 17.15 hrs. information was received by Shri Amiya Sekhar Mondal of Bally Police Station that certain miscreants were about to murder a passenger travelling in a bus near Badamtala Bus Stop. Immediately on receipt of the information Shri Mondal transmitted a message to Bally Police Station and asked for reinforcement, and he himself proceeded to the bus stop. On reaching there he found that people were running about in panic. He left his vehicle and proceeded to the bus stop alone on foot and found that the bus had been cordoned off by about half a dozen young boys armed with pipe guns, bombs, swords and other weapons. Three boys had already entered the driver's cabin in front of the bus and were about to kill a person travelling in the bus. Shri Mondal in disregard of his personal safety broke through the cordon around the bus. He was attacked by the miscreants, but he remained undeterred and fired two rounds from his revolver in self-defence. Shri Mondal then entered the bus and killed two of the miscreants. He then arranged to send the injured passenger to the hospital; and also arrested two of the miscreants. Other miscreants fled away.

In this encounter Shri Amiya Sekhar Mondal exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th May, 1971.

No. 116-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Calcutta Police :—

*Name and Rank of the Officer*

Shri Adhir Chandra Ghosh,  
Constable,  
Special Branch,  
Calcutta.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

Shri Adhir Chandra Ghosh was deployed as security guard for Shri Dhiren Modak, who had sought election to the West Bengal Assembly from the Jorabagan Constituency in the General Elections in 1971. At about 6.30 P.M. on the 20th February, 1971, when Shri Ghosh was accompanying Shri Modak near the crossing of Tarak Chatterjee Lane and B. K. Paul Avenue under the Burtolla Police Station, a bomb was suddenly thrown at them as a result of which Shri Ghosh received an injury from a splinter. Shri Ghosh and Shri Modak immediately took shelter in a shop nearby. Soon thereafter about a dozen men armed with sharp-edged weapons entered the shop and tried to kill both of them. Shri Ghosh received an injury on his waist. Shri Ghosh then drew out his revolver and fired three shots as a result of which two of the miscreants were injured. The miscreants then retreated.

In this encounter Shri Adhir Chandra Ghosh displayed exemplary courage and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th February, 1971.

No. 117-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

*Name and Rank of the Officer*

Shri Dharamkar Ambaji,

Sub-Inspector of Police,

Afzal Gunj,

Hyderabad,

Andhra Pradesh.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

Some Harijans had erected some huts behind the Gurudwara Gowinguda in Hyderabad and were residing there. On the 18th September, 1971, when one Sathiah, a resident of those huts was returning to his house from City Bus Depot, he was stopped by one Jagjeeth Singh near the City Hotel. Jagjeeth Singh asked Sathiah to remove his hut along with other huts and that nobody should reside behind the Gurudwara. In the meantime, a friend of Sathiah happened to pass that way and stopped there to intervene in the matter. Even before Sathiah could explain the matter, Jagjeeth Singh got enraged at the intrusion of the friend of Sathiah. He picked up a stick lying near by and assaulted the friend of Sathiah. Later Jagjeeth Singh threw away the stick and picked up a knife from a fruit vendor and tried to attack the friend of Sathiah. He was, however, prevented by a police constable on duty from doing so. Jagjeeth Singh ran to his house and returned with a sword in his hand. In the meantime the police constable on duty telephoned the Afzalgunj Police Station about the incident. On receipt of the information, Shri Dharamkar Ambaji rushed to the spot with a police party. On seeing Shri Ambaji, Jagjeeth Singh ran towards the Gurudwara. Shri Ambaji deployed his men around the Gurudwara. After some time Jagjeeth Singh came out and threatened to kill Shri Ambaji if the latter did not withdraw his men. In disregard of his personal safety Shri Ambaji tried to arrest Jagjeeth Singh but the latter charged the Sub-Inspector with a sword. Shri Ambaji warded off the attack and clapped the hand of the assailant. A scuffle ensued between Shri Ambaji and Jagjeeth Singh in which the former received injuries on the left elbow and left little finger but he did not loosen the grip over the assailant till the latter was arrested by other members of the police party.

In this action Shri Dharamkar Ambaji displayed conspicuous courage, bravery and determination.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th September, 1971.

No. 118-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

*Name and Rank of the Officer*

Shri Mahipat Singh,

Circle Inspector of Police,

District Datia,

Madhya Pradesh.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

The gang of dacoit Mohna Kachhi had spread a reign of terror in the District of Datia and the neighbouring districts of Gwalior in Madhya Pradesh and Jabalpur and Jhansi of Uttar Pradesh. On the 12th February, 1972, information was received by Shri Mahipat Singh that the gang of Mohna Kachhi was present in village Unchla. A raid was immediately organised and the hide-out of the gang was surrounded. The dacoits came to know about the presence of the police and opened heavy fire on them. A bullet narrowly missed Shri Mahipat Singh, but he remained undeterred and asked the dacoits to surrender. The dacoits, however, continued to fire during the night and at about 0415 hrs. they made an attempt to escape under cover of heavy fire. Shri Mahipat Singh in complete disregard of his personal safety thwarted the attempt of the dacoits and succeeded in shooting down the gang-leader Mohna Kachhi and one more dacoit. He also captured one dacoit alive.

In this encounter Shri Mahipat Singh exhibited conspicuous gallantry, initiative and leadership of high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th February, 1972.

P. N. KRISHNA MANI, Jr. Secy. to the President

## CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 18th November, 1972

### RULES

No. 6/51/72-CS-I.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973 for selection of (i) Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date, but who were commissioned on or after that date, and (ii) Ex-Servicemen, for the purpose of filling vacancies reserved for them in the Services/posts covered by Category I and Category II respectively, as follows, are published for general information in pursuance of the provisions contained in rule 5 of the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules 1971, and rule 4 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and Posts Class II and Class IV) Rules, 1971. (The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules, 1971 and the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Services and Posts Class III and Class IV) Rules 1971 aforesaid shall cease to be in force on and from the 29th January, 1974 and 1st July, 1974 respectively unless extended by Government).

### Category I

#### Class II Services/posts

- (i) Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B);
- (ii) Central Secretariat Service—Assistants Grade;
- (iii) Armed Forces Headquarters, Civil Service—Assistants Grade;
- (iv) Posts of Assistant in the office of the Election Commission, New Delhi;
- (v) Posts of Assistant in the office of the Central Vigilance Commission, New Delhi;
- (vi) Posts of Assistant in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi;
- (vii) Posts of Assistant in the Department of Tourism, New Delhi; and
- (viii) Posts of Assistant in other departments and Attached Offices of the Government of India not included in the IFS(B)/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service.

### Category II

#### Class III Services/posts

- (i) Railway Board Secretariat Service—Grade IV (Assistants); and
- (ii) Posts of Assistant in other departments and Attached Offices of the Government of India not included in the Railway Board Secretariat Service.

Subjects to the provisions of rule 2, a candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N. B. I.—Candidates are required to specify clearly in their applications the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. They are advised to

indicate as many Services/posts as they wish to so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N. B. 11.—No request for addition to or alteration in the order of preferences for the services, posts originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before, 30th November, 1973.

2. (a) Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers will be eligible to compete only for vacancies reserved for them in the posts of Assistants in Class II Services, posts included in Category I.

(b) Ex-Servicemen will be eligible to compete only for vacancies reserved for them in the posts of Assistants in Class III Services/posts included in Category II.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part 'C' States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modifications) Order 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order 1956 the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. Subject to the provisions of these rules, the following categories of Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November 1962 but before the 10th January 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date but who were commissioned on or after that date will be eligible to appear at this examination,—

(i) Officers who have been released during 1972 prior to the date of this Notification or are due to be released thereafter till the end of 1973—

(ii) Officers mentioned in rule 12 to the extent and in accordance with the provisions of that rule.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, "release" means :—

(i) release as per the Scheduled year of release.

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service from the Armed Forces after a spell of service, and not during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers, the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure of 3 or 5 years, as the case may be, as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person shall be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to the examination.

6. Subject to the provisions of these Rules, all Ex-Servicemen will be eligible to appear at this examination.

NOTE.—For the purpose of these rules, "Ex-Serviceman" means a person who has served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months as on 15th January, 1973, and,—

(i) has been released, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(ii) has to serve for not more than six months as on 15th January, 1973, for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid.

Explanation.—For the purpose of this Rule, "Armed Forces of the Union" means the Naval, Military or Air Forces of the Union and includes the Armed Forces of the Former Indian States.

7. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(f) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Grade IV of the General Cadre (Assistant) of the Indian Foreign Service (B).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

8. (A) An Emergency Commissioned Officer/Short Service Commissioned Officer seeking admission to the examination under Rule 5 above must not have attained the age of 24 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-Commissioned training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training).

Provided that a candidate applying for admission to this examination under Rule 9(b) below must not have attained on the aforesaid date the age of :—

(i) 24 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the

year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

- (ii) 23 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);
- (iii) 22 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the 2nd year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);
- (iv) 21 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the 3rd year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);
- (v) 20 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the fourth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training); and
- (vi) 19 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the fifth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(B) An Ex-Serviceman seeking admission to the examination under rule 6 above, must have attained on 1st January, 1973, the age of 20 years and must not have attained an age exceeding 25 years by more than his total service in the Armed Forces increased by three years.

NOTE.—The period of "call up service" of an ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 8(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.
- (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;
- (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964; under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

(xii) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage.

(D) The age limit prescribed in sub-para (A) above will also be relaxable :—

(i) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963; is a *bona fide* displaced person from Pakistan.

(ii) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(iii) up to a maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(iv) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Sri Lanka (formerly known as Ceylon).

NOTE 1.—The provisions contained in rule 8(D)(i) and 8(D)(ii) will not apply to candidate mentioned at Sl. Nos. (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 8(A).

NOTE 2.—The provisions contained in rule 8(D)(iii) and 8(D)(iv) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 8(A) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1963.

The provisions contained in rule 8(D)(iii) and 8(D)(iv) will not apply to candidate mentioned at Sl. No. (ii) in proviso to Rule 8(A) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1964.

(E) The Freedom Fighters of Goa, Daman and Diu who were not employees of the Portuguese Government of Goa, Daman and Diu and participated in the liberation struggle and suffered as a consequence thereof; imprisonment or detention for not less than six months under former Portu-

guese Administration, will be permitted to appear at the examination provided they have not attained the age of 35 years on 1-1-1972.

NOTE.—Candidates claiming age concession under rule 8(E) above will not be entitled to the age concessions allowed under rule 8(C) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

9.(a) An Emergency Commissioned Officer/Short Service Commissioned Officer seeking admission to the examination under Rule 5 above, must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Provided that—

- (i) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate if he has passed examinations conducted by other institution, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.
- (ii) a candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

NOTE.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination *vide* Sub-Rule (a) of this Rule, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

(b) A candidate who, when he appeared before a Services Selection Board as a candidate for the grant of Emergency Commission/Short Service Commission in the Armed Forces was studying in a recognised institution, e.g., a university/an institution affiliated to a university for the award of any of the qualifications prescribed in sub-Rule (a) of this Rule, but who having discontinued his studies because of joining the Armed Forces, had not acquired such qualification will also be eligible to appear at the examination.

(c) An Ex-Serviceman seeking admission to the examination under Rule 6 above must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Union Public Service Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Union Public Service Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Union Public Service Commission.

10. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination held in 1971.

11. A candidate competing for services and posts in category 1 (see rule 2) must take the examinations, held in the year of his release and in the year following the year of his release, as his first and second chances respectively.

12. Notwithstanding anything contained in rule 11—

- (i) a candidate invalidated owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1971 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination may take the examination to be held in 1973, as his second chance;
- (ii) a candidate invalidated owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1972 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972 examination may take the examination to be held in 1973 as his first chance;
- (iii) an Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officer who joined the pre-Commission training in the Armed Forces before 10-1-1968 but was commissioned on or after 10-1-1968 may take the examination to be held in 1973, subject to the conditions indicated below—
  - (a) as his second chance, if released prior to 1972;
  - (b) as his first chance, if released during 1972;
  - (c) as his first chance, if invalidated owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1971 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination.

NOTE 1.—The provisions contained in (i) and (iii)(c) above will not apply to candidates who were due for release in 1971.

NOTE 2.—The provisions contained in (ii) above, will not apply to candidates who were due for release in 1972.

NOTE 3.—Candidates who in terms of the provisions of this rule, are eligible to take their second chance in 1974, may avail of the same, if the provisions of the Rules referred to in rule 1 of these Rules are extended by Government beyond the 20th January, 1974.

13. No person

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

14. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding of his unit who will forward it to the Union Public Service Commission.

All other candidates in Government Service whether in a permanent or on temporary capacity or as a casual or daily-rated employees, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

15. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

17. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

18. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

19. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

20. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have tampered with or of making statements which are incorrect or false or suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution:—

(a) be debarred permanently or for a specified period:

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

21. After the examination—

(a) the candidates competing for Services/posts included in Category I will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment; and

(b) the candidates competing for Services/posts included in Category II will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment with due regard to the number of vacancies available to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

22. If on the result of the examination a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers in Category I Services/posts and for Ex-Servicemen in Category II Services/posts, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

23. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

24. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for the various Services/posts included in the Category (c.f. Rule 1) in respect of which he has been admitted to the examination.

25. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

26. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

27. Conditions of Service for Assistants' in the Central Secretariat Service, Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Armed Forces Headquarters Civil Service, the posts of Assistants' in the Election Commission of India, and the Department of Tourism, Central Vigilance Commission and Department of Parliamentary Affairs, are briefly stated in Appendix III.

M. K. VASUDEVAN,  
Under Secy.

#### APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India  
(Vide Rule 9)

##### *Indian Universities*

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

##### *Universities in Burma*

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

##### *English and Welsh Universities*

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

##### *Scottish Universities*

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

##### *Irish Universities*

The University of Dublin (Trinity College). The National University of Ireland. The Queen's University, Belfast.

##### *Universities in Pakistan*

The University of Punjab. The University of Sind.

##### *Universities in Bangladesh*

The Dacca University.

The Rajshahi University.

##### *University in Nepal*

The Tribhuvan University, Kathmandu.

#### APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (Vide Rule 9).

1. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapeeth, Varanasi.
3. French Examination "Propedeutique".
4. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
5. Diploma in Rural Services of the Visva Bharti University.
6. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.



7. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.
8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
9. 'Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full" student.
10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects i.e. Varishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Viswa-Vidyalaya, Varanasi.
11. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

#### APPENDIX II

##### 1. The competitive examination comprises :

- (a) Written examination in three subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 400 marks.
- (b) Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces in the case of Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers, carrying a maximum of 100 marks.

##### 2. The subjects of the examination the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows:—

	Max. Marks	Time Allowed
1. Essay .. .. .	100	2 hours
2. General English .. .. .	200	3 hours
3. General Knowledge including Geography of India .. .. .	100	2 hours

##### 3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 3 or both, either in Hindi or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi should indicate their intention to do so in col. 10 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed to help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

#### SCHEDULE

##### SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) Essay : An essay to be written on one of the several specified subjects.

##### (2) General English :

- (i) Precis writing and drafting : Questions to test the understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary or precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.
- (ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.
- (iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language.

##### (3) General Knowledge including Geography of India :

Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature which candidates should be able to answer without special study.

#### APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

##### (i) Indian Foreign Service (B)

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Foreign Trade, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) excluding Grades lower than Grade IV are as follows :—

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad.	Rs. 900-50-1250.
Integrated Grade II and III	Attaches and Section Officers at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad.	Rs. 350-25-500-30-500-FB-30-800-FB-30-830-35-900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions and Posts abroad.	Rs. 210-10-270-15-300-FB 15-450-EB-20 250.

NOTE.—Assistants promoted to the Integrated Grade II and III are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

2. Candidates selected for Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the IFS(B) will be appointed initially against temporary vacancies. They will, however, be confirmed, if otherwise eligible, in their turn in accordance with the Indian Foreign Service 'B' (Recruitment Cadre seniority and Promotion) Rules, 1964, depending on the availability of substantive vacancies. Appointment to Grade IV, will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission subject to the rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed



by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from Service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service, and the Railway Board Secretariat Service. Further, all such persons will be liable to serve in any post either in India or abroad, to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families, etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the I.F.S. (B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S. (B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B), (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE.—In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior Scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 900-50-1,000-60-1,600-50-1,800.

#### (ii) Central Secretariat Service

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

- (1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) = Rs. 1,100-50-1,300-60-1,600-100-1,800.
- (2) Grade I (Under Secretary or equivalent) = Rs. 900-50-1,250.
- (3) Section Officers Grade = Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.
- (4) Assistant Grade = Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for the Service will not, after such appointment, have any

claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

#### (iii) Railway Board Secretariat Service

(a) The service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as Recruitment, Training, Promotion etc. are concerned are regulated by the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, which are broadly similar to the Central Secretariat Service Rules, 1962.

(b) The Railway Board Service consists of the following grades :

(i) Selected Grade: such posts in the grade of Joint Directors/Dy. Secretary Railway Board as may from time to time be held by officers of the Railway Board Secretariat Service.	Rs. 1100-50-1300-60-1600-100-1,800.
(ii) (a) Dy. Directors Grade: such posts of Dy. Directors, Railway Board as may from time to time be held by officers of the Railway Board Secretariat Service.	Rs. 900-50-1,250- plus special pay of Rs. 200/- p.m.
(b) Grade I: Assistant Director & Under Secretaries.	Rs. 900-50-1,250
(iii) Section Officer Grade	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.
(iv) Assistants Grade	Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

(c) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(d) Officer recruited direct as Assistants will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge from the service.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(g) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(h) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway Officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

#### (iv) The Armed Forces Headquarters Civil Service.

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present five grades as follows :—

- (1) Joint Director (Class I)—Rs. 1300-60-1600.
- (2) Senior Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 1,100-50-1,400.

- (3) Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 740—30—800—50—1,150.
- (4) Assistant Civilian Staff Officer (Class II—Gazetted)—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.
- (5) Assistant (Class II—Non-gazetted)—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 400 in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period or probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grades of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

#### (v) Election Commission, India

The posts of Assistants in the Election Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Assistants in the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the Central Secretariat Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

2. The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. The next two higher grades are—

- (1) Section Officers' Grade—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
- (2) Under Secretary's Grade—Rs. 900—50—1,250.

#### (vi) Department of Tourism

The posts of Assistants in the Department of Tourism carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 as prescribed for Grade IV of the Central Secretariat Service. These posts are, however, not

included in the C.S.S. Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to the posts included in the cadre of the C.S.S.

The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government from time to time. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in the discharge of the probationer from service.

On completion of the probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work, or conduct, has, in the opinion of the Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as the Government may consider necessary.

Assistants will be eligible for promotion to higher grade of Assistant Director (Administration) in the pay scale of Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800 in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

#### (vii) Central Vigilance Commission

The posts of Assistants in the Central Vigilance Commission carry the same scale of pay as is prescribed for Grade IV of the Central Secretariat Service viz. Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530. These posts are, however, not included in the Central Secretariat Service and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to the posts included in the cadre of the C.S.S.

2. The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or pass the test may result in the discharge of the appointee from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the appointee in his appointment subject to availability of vacancies, or if his work or conduct has, in the opinion of the appointing authority been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as the appointing authority may consider necessary.

Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions of the rules in force from time to time in this behalf. The next higher grades at present are :

- (1) Section Officer Grade (Class II—Gazetted)—Rs. 350 (400)—25 — 500—30 — 590—EB—30 — 800—EB—30—830—35—900.
- (2) Under Secretary's Grade (Class I)—Rs. 900—50—1,250.

#### (viii) Department of Parliamentary Affairs

The posts of Assistants in the Department of Parliamentary Affairs carry a scale of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Assistants in the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the Central Secretariat Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

2. The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as

may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationers from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment provided permanent posts are available and his turn for confirmation has come or if his work or conduct, has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. The next two higher grades are—

- (1) Section Officers' Grade—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 (Class II).
- (2) Under Secretaries' Grade—Rs. 900—50—1250 (Class I).

NOTE.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Section Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 400/- in the scale for the grade of Section Officer.

